REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 6 | MARCH - 2026

"सीमापार आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर की आंतरिक स्थिरता : एक नीतिगत अध्ययन

विजय बहादुर साकेत
शोधार्थी राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. गायत्री मिश्रा
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

कश्मीर समस्या भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे जटिल और दीर्घकालिक राजनीतिक–सुरक्षा चुनौतियों में से एक रही है। विशेष रूप से सीमापार आतंकवाद ने न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है, बल्कि जम्मू–कश्मीर की आंतरिक स्थिरता, सामाजिक समरसता और विकास प्रक्रिया को भी गंभीर रूप से बाधित किया है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य सीमापार आतंकवाद की प्रकृति, उसके स्रोत, उसके रणनीतिक आयाम तथा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। साथ ही, यह अध्ययन कश्मीर की आंतरिक स्थिरता के विभिन्न संकेतकों राजनीतिक सहभागिता, प्रशासनिक सुदृढ़ता, सामाजिक विश्वास, तथा आर्थिक विकासकृपर आतंकवाद के प्रभाव का सम्यक परीक्षण करता है। अनुच्छेद 370 के निरसन के पश्चात सुरक्षा परिदृश्य में आए परिवर्तनों, केंद्र–राज्य संबंधों की नई संरचना तथा सुरक्षा बलों की रणनीतिक प्रतिक्रियाओं को भी इस अध्ययन में नीतिगत दृष्टिकोण से परखा गया है। द्वितीयक स्रोतोंकृसरकारी रिपोर्टों, विद्वानों के शोध कार्यों, सुरक्षा विश्लेषणों एवं नीति दस्तावेजोंकृके आधार पर यह शोध यह प्रतिपादित करता है कि सीमापार आतंकवाद केवल सैन्य चुनौती नहीं, बल्कि एक बहुआयामी राजनीतिक–सामाजिक समस्या है। अतः इसके समाधान हेतु समन्वित सुरक्षा नीति, कूटनीतिक पहल, विकासोन्मुख कार्यक्रमों और स्थानीय जनसहभागिता की आवश्यकता है। यह अध्ययन राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के मध्य अंतर्संबंध को स्पष्ट करते हुए एक संतुलित नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर बल देता है।

मुख्य शब्द : सीमापार आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, कश्मीर, आंतरिक स्थिरता, अनुच्छेद 370, उग्रवाद, सुरक्षा नीति

प्रस्तावना –

कश्मीर समस्या भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी एक जटिल राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रही है। 1947 में जम्मू–कश्मीर रियासत के भारत में विलय के पश्चात से ही यह क्षेत्र भारत–पाकिस्तान संबंधों का केंद्रीय बिंदु बना रहा। समय–समय पर हुए युद्धों, कूटनीतिक वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेपों के बावजूद यह समस्या पूर्णतः समाधान की ओर अग्रसर नहीं हो सकी। विशेष रूप से 1989 के पश्चात कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद की तीव्रता में वृद्धि हुई, जिसने क्षेत्र की आंतरिक स्थिरता

को गंभीर रूप से प्रभावित किया। सीमापार आतंकवाद का आशय उन आतंकी गतिविधियों से है, जिनका संचालन, वित्तपोषण, प्रशिक्षण या समर्थन किसी अन्य राष्ट्र की भूमि से होता है और जिनका लक्ष्य दूसरे राष्ट्र की आंतरिक शांति एवं सुरक्षा को बाधित करना होता है। कश्मीर के संदर्भ में यह तथ्य अनेक बार प्रमाणित हुआ है कि आतंकवादी संगठनों को सीमा पार से समर्थन प्राप्त होता रहा है। यह स्थिति न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए भी एक दीर्घकालिक खतरा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना केवल सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है। आधुनिक राजनीतिक विमर्श में राष्ट्रीय सुरक्षा में आंतरिक शांति, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता और संस्थागत सुदृढ़ता भी सम्मिलित हैं। जब किसी राज्य की सीमाओं के बाहर से हिंसात्मक गतिविधियाँ संचालित होकर उसके आंतरिक तंत्र को प्रभावित करती हैं, तब वह समस्या केवल कानून–व्यवस्था का विषय नहीं रह जाती, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन जाती है।

कश्मीर में सीमापार आतंकवाद ने स्थानीय युवाओं के मनोविज्ञान, सामाजिक ताने–बाने और प्रशासनिक संरचना को प्रभावित किया है। हिंसा, अस्थिरता और अविश्वास का वातावरण विकासात्मक पहलों को बाधित करता है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनविश्वास को कमजोर करता है। पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों में भागीदारी, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र की स्थिति, निवेश के अवसर ये सभी कारक आंतरिक स्थिरता के संकेतक हैं, जो आतंकवाद की तीव्रता से प्रभावित होते रहे हैं।

5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 एवं 35 के प्रावधानों को निरस्त कर जम्मू–कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। इस कदम को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकीकरण और सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात सुरक्षा परिदृश्य, प्रशासनिक नियंत्रण और विकासात्मक कार्यक्रमों में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। तथापि सीमापार आतंकवाद की चुनौती पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है।

नीतिगत दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हम सीमापार आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के मध्य अंतर्संबंध को समग्रता में समझें। केवल सैन्य उपाय पर्याप्त नहीं हैंय कूटनीतिक दबाव, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, सीमा प्रबंधन, खुफिया तंत्र की सुदृढ़ता, तथा स्थानीय जनविश्वास निर्माण जैसे उपाय भी अनिवार्य हैं।

प्रस्तुत अध्ययन इसी बहुआयामी संदर्भ में कश्मीर की स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार सीमापार आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है और आंतरिक स्थिरता को चुनौती देता है, तथा इन चुनौतियों के समाधान हेतु कौन–से नीतिगत उपाय प्रभावी हो सकते हैं।

शोध उद्देश्य –

कश्मीर की समस्या को समझने के लिए केवल ऐतिहासिक या राजनीतिक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं हैय बल्कि इसे समकालीन सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में भी परखना आवश्यक है। सीमापार आतंकवाद ने इस क्षेत्र को लंबे समय तक हिंसा और अस्थिरता की स्थिति में रखा है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक अवधारणा तथा आंतरिक स्थिरता के संकेतकों का तुलनात्मक अध्ययन करना प्रासंगिक हो जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. सीमापार आतंकवाद की प्रकृति, स्वरूप एवं उसके स्रोतों का विश्लेषण करना।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीमापार आतंकवाद के प्रभाव का परीक्षण करना।
3. कश्मीर की आंतरिक स्थिरता के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आयामों का अध्ययन करना।
4. वर्तमान सरकारी नीतियों एवं सुरक्षा रणनीतियों का नीतिगत मूल्यांकन करना।

उक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि –

प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों एवं स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन के लिए सरकारी रिपोर्टें, गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय के प्रकाशन, संसद में प्रस्तुत प्रतिवेदन, नीति दस्तावेज, विद्वानों द्वारा प्रकाशित शोध ग्रंथ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सुरक्षा अध्ययन से संबंधित पत्रिकाएँ तथा प्रतिष्ठित समाचार स्रोतों का उपयोग

किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) एवं अन्य आधिकारिक सांख्यिकीय स्रोतों के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। विषय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तथ्यों की पुष्टि विश्वसनीय एवं प्रमाणिक स्रोतों से की गई है। नीतिगत विश्लेषण हेतु तुलनात्मक एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे अध्ययन अधिक संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ बन सके।

विश्लेषण –

कश्मीर में सीमापार आतंकवाद का स्वरूप बहुआयामी रहा है। प्रारंभिक चरण में यह स्थानीय असंतोष एवं राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ा था, परंतु शीघ्र ही इसे बाहरी समर्थन प्राप्त होने लगा। प्रशिक्षण शिविरों, वित्तीय सहायता और वैचारिक समर्थन ने आतंकवादी गतिविधियों को संगठित स्वरूप प्रदान किया। परिणामस्वरूप 1990 के दशक में हिंसात्मक घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई, जिसने हजारों नागरिकों और सुरक्षा बलों के जीवन को प्रभावित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह स्थिति गंभीर थी, क्योंकि सीमा पार से प्रायोजित गतिविधियाँ भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दे रही थीं। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की घटनाएँ, हथियारों की तस्करी तथा संचार नेटवर्क का दुरुपयोग सुरक्षा तंत्र के लिए निरंतर चुनौती बने रहे। भारत ने इसके प्रत्युत्तर में सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ किया, बाड़बंदी की, निगरानी तंत्र को आधुनिक बनाया तथा आतंकवाद–रोधी अभियानों को तेज किया।

आंतरिक स्थिरता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि निरंतर हिंसा ने सामाजिक ताने–बाने को कमजोर किया। विस्थापन, भय और अविश्वास का वातावरण सामान्य जीवन को बाधित करता रहा। शिक्षा संस्थानों, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी प्रभावित हुई, यद्यपि समय–समय पर हुए चुनावों में जनता की सहभागिता ने यह संकेत दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था बनी रही।

अनुच्छेद 370 के निरसन के पश्चात केंद्र सरकार ने सुरक्षा सुदृढ़ीकरण, निवेश प्रोत्साहन, अवसंरचना विकास और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया है। हिंसक घटनाओं में कुछ कमी के संकेत मिले, किंतु सीमापार से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या का समाधान केवल संवैधानिक परिवर्तन से संभव नहीं, बल्कि निरंतर सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है।

नीतिगत दृष्टि से भारत ने बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है, आंतरिक सुरक्षा अभियानों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के विरुद्ध समर्थन जुटाना, वित्तीय नेटवर्क पर नियंत्रण, तथा पड़ोसी देशों के साथ वार्ता। इसके अतिरिक्त स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन और पुनर्वास कार्यक्रमों पर बल दिया गया है, जिससे उग्रवाद की ओर झुकाव को कम किया जा सके। इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीमापार आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। यदि बाहरी समर्थन समाप्त नहीं होता, तो आंतरिक स्थिरता की प्रक्रिया बाधित होती रहती है। अतः समन्वित, संतुलित और दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सीमापार आतंकवाद केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समरसता के लिए व्यापक खतरा है। कश्मीर के संदर्भ में यह समस्या ऐतिहासिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय आयामों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है, जिसमें सैन्य शक्ति के साथ–साथ सामाजिक विश्वास, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता भी सम्मिलित हों। अनुच्छेद 370 के निरसन के पश्चात प्रशासनिक और विकासात्मक स्तर पर परिवर्तन हुए हैं, परंतु स्थायी समाधान के लिए सतत सुरक्षा प्रबंधन और कूटनीतिक सक्रियता अनिवार्य है। अतः यह कहा जा सकता है कि सीमापार आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी नीति में कठोर सुरक्षा उपायों के साथ–साथ संवाद, विकास और जनसहभागिता को समान महत्व देना होगा। केवल इसी संतुलित दृष्टिकोण से कश्मीर की आंतरिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को दीर्घकालिक आधार प्रदान किया जा सकता है।

संदर्भ –

1. बसु, दुर्गा दास, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेक्सिसनेक्सिस, नई दिल्ली, 2021
2. भारत सरकार, वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, 2023
3. गांगुली, सुमित, कॉन्फ्लिक्ट अनएंडिंग : इंडियादृपाकिस्तान टेंशंस सिंस 1947, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2019
4. गुप्ता, शेखर, एंटिसिपेटिंग इंडिया'ज सिक्योरिटी चौलेंजेस, हार्परकॉलीन्स, नई दिल्ली, 2020
5. रक्षा मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2023
6. स्कोफील्ड, विक्टोरिया, कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट, आई.बी. टॉरिस, लंदन, 2021